(संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and Its Territory)

संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद 1 के अनुसार- भारत राज्यों का एक संघ (a Union of States) है।

(Part-1 of the Constitution, Articles 1 to 4 are about the Union and its territories. According to Article 1, India is a Union of States.

अनुच्छेद-2- संसद को संघ में नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।

Article-2- Empowers Parliament to make laws for the entry or establishment of new states in the Union.

अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है

According to Article-3, Parliament can form a new state and change the area, boundary or name of an existing state by a simple majority.

संसद द्वारा अनुच्छेद-2 अथवा अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि अनु. 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जायेगी (अनुच्छेद-4)

A law made by Parliament under Article 2 or Article 3 shall not be deemed to be a law amending the Constitution for the purposes of Article 368 (Article 4)

बेरुबाड़ी मामलें में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में, क्या किसी राज्य या उसके भू-भाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है?

1960

In the Berubari case, the question came up for opinion before the Supreme Court whether the power of Parliament to alter the areas and boundaries of States under Article 3 includes the power to cede any State or any part of its territory to a foreign State?

Art 3 ⇒ संसद

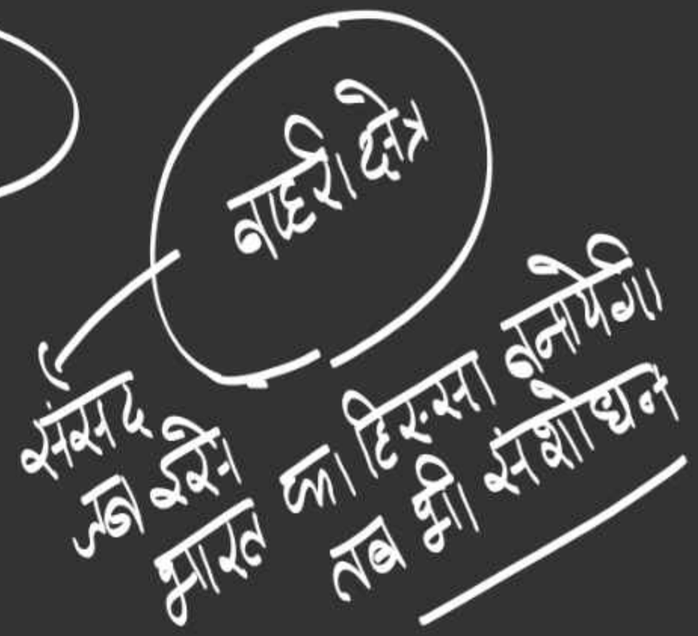
- राज्य का गठन
- क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

⇒ साधारण बहुमत

Q ⇒ क्या संसद भारत के किसी भाग Art 3 के तहत अन्य देश को दे सकती है?

⇓

नहीं, ऐसा करने के लिए संसद को संविधान में संशोधन (Amendment) करना होगा।



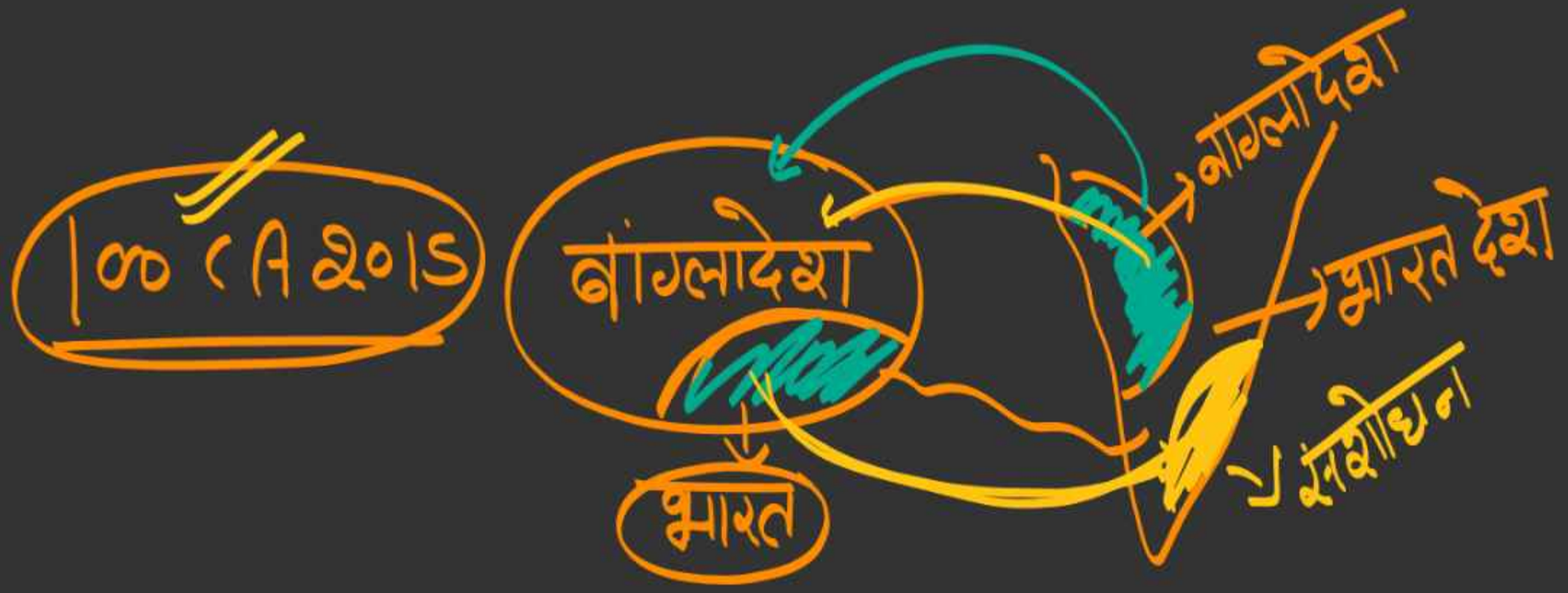
न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद-368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा।

The court said that the Parliament cannot do this through ordinary law. For this, a constitutional amendment will have to be made under Article 368.

अतः संसद द्वारा 9वाँ संविधान संशोधन (1960) पारित कर बेरुबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया।

क्षेत्र पाक०

So, the Berubari Union Territory was handed over to Pakistan by passing the 9th Constitutional Amendment (1960) by the Parliament and some Indian territories were handed over to Bangladesh by the 100th Constitutional Amendment Act 2015.


CAA 2015
बांग्लादेश
भारत
बांग्लादेश
भारत देश
संशोधन


INDIA
States and Union Territories
TAJIKISTAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
CHINA (TIBET)
NEPAL
BHUTAN
BANGLADESH
MYANMAR (BURMA)
SRI LANKA
LADAKH
Srinagar
Leh
JAMMU & KASHMIR
Jammu
HIMACHAL PRADESH
Shimla
PUNJAB
Chandigarh
Dehradun
UTTARAKHAND
HARYANA
DELHI
New Delhi
UTTAR PRADESH
Lucknow
Jaipur
RAJASTHAN
SIKKIM
Gangtok
ARUNACHAL PRADESH
Itanagar
Dispur
ASSAM
NAGALAND
Kohima
Shillong
MEGHALAYA
Imphal
MANIPUR
BIHAR
Patna
Agartala
TRIPURA
Aizawl
MIZORAM
JHARKHAND
Ranchi
WEST BENGAL
Kolkata
Gandhinagar
GUJARAT
Bhopal
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
Raipur
ODISHA
Bhubaneswar
BAY OF BENGAL
Daman
Silvassa
DAMAN & DIU
DADRA & NAGAR HAVELI
MAHARASHTRA
Mumbai
TELANGANA
Hyderabad
Amaravati
Yanam (Puducherry)
ARABIAN SEA
Panaji
GOA
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
Bengaluru
Chennai
Mahe (Puducherry)
PUDUCHERRY
Kavaratti
LAKSHADWEEP (INDIA)
KERALA
TAMIL NADU
Karaikal (Puducherry)
Thiruvananthapuram
Palk Strait
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS (INDIA)
Port Blair
International Boundary
State/UT Boundary
Country Capital
State/UT Capital
Map not to Scale
INDIAN OCEAN
Copyright © 2019 www.mapsofworld.com

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन Reorganization of states on linguistic basis

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने ~~27 नवम्बर, 1947~~ June 1948 को न्यायमूर्ति एस. के. धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय' भाषायी प्रान्त आयोग' (Linguis- tic Provinces Commission) का गठन किया। ✓

धर आयोग

After independence, in view of the demand for reorganization of states on linguistic basis, Constituent Assembly Chairman Dr. Rajendra Prasad constituted a four-member 'Linguis- tic Provinces Commission' under the chairmanship of Justice S.K. Dhar on ~~27 November 1947~~. (June 1948)

धर आयोग ⇒ गठन ⇒ June 1948

- डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा गठन
- अध्यक्ष ⇒ एस० के० धर
- सदस्य ⇒ 5
- क्या भाषायी आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं ?
- रिपोर्ट ⇒ नहीं।
  - 10 Dec. 1948

आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

In its report presented on 10 December 1948, the commission suggested reorganization of states on the basis of administrative, geographical, financial and developmental convenience instead of language.

⇒ इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर
1948 में JVP समिति का गठन किया गया।

जवाहर लाल नेहरु, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीता रमैया (JVP) की तीन सदस्यीय समिति गठित किया था। इस समिति ने भी 1 अप्रैल, 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया।

१९४९

A three-member committee of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sita Ramaiya (JVP) was formed. This committee also opposed the reorganization of states on linguistic basis in its report presented on 1 April 1949.

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 56 दिनों बाद 15 दिसम्बर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

58

Supporting the demand for formation of a separate state on the basis of language for Telugu speakers, Potti Sri Ramulu started a fast unto death, who died 56 days later on 15 December 1952.

58

56 + 2 ⇒ 58

56 days ⇒ तबियत खराब ⇒ अस्पताल (Hospital) ⇒ 2 लोग। ⟶ 2 दिन बाद Death

आमरण अनशन

फलस्वरुप प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।*

As a result, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a separate state for Telugu speakers, Andhra Pradesh. It was formed on 1 October 1953. It was the first state to be formed on linguistic basis.*

Q => भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य? (1 Oct. 1953)

Q => रामुलु की मृत्यु कब हुई?

Q => " " " (कितने दिनों में?)

तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा-भाषियों द्वारा अलग राज्य की माँग भी तेज हो गयी; जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय [redacted] सदस्य थे-

After the formation of a separate state for Telugu speakers, the demand for a separate state by other language speakers also intensified; for which a three-member committee headed by Justice Fazal Ali was considered in 1953-

फजली अली आयोग → गठन → 1953
→ अध्यक्ष → न्यायमूर्ति फजल अली, अन्य सदस्य - 2
→ कुल सदस्य → 3

राज्य पुनर्गठन आयोग
हृदयनाथ कुंजरू
के० एम० पनिक्कर

के.एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरु) 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (The States Re-orga- nization Commission) गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 पारित किया गया।

K.M. Panikkar and Hriday Nath Kunzru) 'The States Reorganization Commission' was formed. This commission submitted its report to the Central Government on 30 December 1955. On the basis of this report, the States Reorganization Act-1956 was passed